राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र

हलधर किसान

डाक पंजी. क्र.- MP/KDW/93/2023-24 Email id: haldharkisankgn@gmail.com RNI NO. MPHIN/2022/85285

वर्ष 03 अंक 06 सितंबर 2024 पृष्ठ- 8 मूल्य- 5.00 रुपए

डिजीटल कृषि नीति किसानों की आजीविका के लिए खतरा...!

किसान संगठनों का आरोप इससे कार्पोरेट जगत को मिलेगा फायदा

हलधर किसान

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से हाल में घोषित डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन सहित 14 हजार करोड़ रुपये की सात योजनाओं को लेकर किसान संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है।

अखिल भारतीय किसान सभा ने केंद्र सरकार की डिजिटल कृषि मिशन नीति पर सवाल खड़े करते हुए इस नीति को किसानों की आजीविका लिए खतरा करार दिया है। किसान सभा के पदाधिकारियों ने बैठक कर आहूत कर कहा है कि इस नीति के तहत जो योजनाएं शुरू की जानी हैं वह कॉर्पोरेटीकरण की एक सोची.समझी योजना का हिस्सा है। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक धवले ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह किसानों के हितों में कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाए। इसके अलावा एमएसपी सुनिश्चित करें। फिलहाल संगठन ने किसानों को अगले बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा है।। बैठक में किसान सभा से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि 1400 करोड़ रुपए वाले डिजिटल कृषि मिशन से किसानों का कोई सीधा हित नहीं है। संघ के अध्यक्ष अशोक धवले कहते हैं कि भारतीय किसानों का बड़ा हिस्सा छोटेए सीमांतए भूमिहीन और बटाईदार किसानों का है। उनका आरोप है कि यदि इन तबकों को बड़े व्यवसाय के नेतृत्व वाले डिजिटलीकरण में शामिल किया जाता है तो निगम पूरे कृषि उत्पादन पर हावी हो सकते हैं। ऐसी दशाओं में किसानों की आजीविका पर दुष्प्रभाव पड़ना तय है।

नई योजना का सीधे तौर पर किया जा रहा कॉर्पोरेटीकरण

संघ से जुड़े किसान नेताओं ने इस दौरान कहा कि मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे में इस नई योजना से सीधा किसान लाभान्वित होगा इसकी संभावना भी न के बराबर दिख रही है। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस नई योजना का सीधे तौर पर कॉर्पोरेटीकरण किया जा रहा है। जिसका लाभ बड़े औद्योगिक घरानों को मिलेगा। इसलिए उनका संगठन इसका विरोध कर रहा है।

केंद्र सरकार की मुक्त बाजार की चाहत. एआईकेएस

अखिल भारतीय किसान सभा ने कहा कि कृषि में शोध के आधुनिकीकरण के लिए घोषित योजना में केंद्र सरकार की मुक्त बाजार की चाहत साफ दिख रही है। उन्होंने इस बैठक के दौरान किसानों से अपील की है। की की एनडीए सरकार की इस नीति का विरोध किया जाए। संगठन ने मांग की है की केंद्र सरकार सभी कृषि इनपुट पर जीएसटी हटाकर उत्पादन लागत कम करे। इसके अलावा छोटे और मध्यम किसानों तथा खेत मजदूरों को प्राथमिकता देकर किसानों के कर्ज माफ करें।

क्या है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन?

डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके किसानों की आय बढ़ाना और कृषि उत्पादकता में सुधार करना है। इस मिशन के माध्यम से किसानों को कृषि से जुड़ी विभिन्न सेवाएं जैसे कि मौसम की भविष्यवाणीए बीज की गुणवत्ताए कीटनाशकों का उपयोग और बाजार की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त होगी।

क्या है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का उद्देश्य?

इस मिशन का मकसद डिजिटल उपकरणों और प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को कृषि संबंधी जानकारी और सेवाएं प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। साथ ही उन्नत कृषि तकनीकों, जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाकर कृषि उत्पादकता में सुधार करना है। कृषि लागत कम करने के साथ नवाचार को प्रोत्साहित करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है।

खेती की आधुनिक तकनिक सीखने सरकारी खर्च पर इजराइल जाएंगे 100 युवा किसान

हलधर किसान, राजस्थान। प्रदेश सरकार कृषि को लेकर नित नए नवाचार करने का प्रयास कर रही है और किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए भी काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने 100 युवा किसानों को इजराइल भेजने का बड़ा फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने नॉलेज एन्हांसमेंट प्रोग्राम शुरू किया है।

ऐसा होने से किसानों को खेती का अनुभव, ज्ञान और रोजगार में लाभ होगा। आवंटित कुल लक्ष्य में से 75 प्रतिशत कृषकों का चयन खंड स्तर पर तथा शेष 25 का चयन राज्य सरकार के स्तर पर किया जाएगा। इसको लेकर उद्यान आयुक्तालय के आयुक्त जयसिंह ने प्रदेश के सभी संयुक्त निदेशक उद्यान के अधिकारियों को निर्देश जारी कर किसानों से ऑनलाइन आवेदन कराने के लिए कहा है।

श्रीडूंगरगढ़ कृषि विभाग के उप.निदेशक कल्प वर्मा ने बताया की नॉलेज एन्हांसमेंट प्रोग्राम के तहत 100 युवा और प्रगतिशील किसानों को इजराइल और अन्य देशों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। इस योजना का उद्देश्य किसानों को नई और उन्नत कृषि तकनीकों से परिचित कराना है, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी।

सरकार अपने खर्च पर भेजेगी विदेश

उच्च पशुपालन तकनीकों का उपयोग करने वाले पशुपालकों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृषक और पशुपालक का चयन विभागीय कमेटी स्कोर क्राइटेरिया के आधार पर किया जाएगा, इसमें उनकी शिक्षा, अनुभव और तकनीकी दक्षता को ध्यान में रखा जाएगा। चयनित किसानों को विदेश भेजने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की जाएगी। विदेश से लौटने के बाद, किसानों को अपने अनुभवों को अन्य किसानों के साथ साझा करना जरूरी होगा।

किसान खेत में नई तकनीक का कर सकेंगे प्रयोग

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कल्प वर्मा ने बताया कि विदेश में जाकर आने वाले किसान भी उन्नत कृषि तकनीकों के लाभ से अवगत हो सकेंगे। उन्हें अपनी खेती में लागू कर सकेंगे। इस योजना के जरिए किसानों को दुनिया की नई.नई कृषि तकनीक के साथ.साथ कृषि उपकरण और संसाधनों के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी।

विदेश यात्रा से मिले अनुभव के आधार पर वो अपने खेत में भी नई तकनीक से खेती कर अपनी उपज बढ़ा सकेंगे। इस बारे में किसानों का कहना है कि राजस्थान की कृषि केवल मानसून पर आधारित है। विदेश में प्रशिक्षण मिलने के बाद उन्हें नई.नई तकनीक और कृषि नवाचारों के बारे में जानकारी मिलेगी, जिसका लाभ वे राजस्थान में कृषि के नवाचार और फसलों के उत्पादन में कर सकेंगे। किसान 10 सितंबर तक राजकिसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश के हर जिले में किसान न्याय यात्रा निकालेगी कांग्रेस, 20 सितं. को एमएसपी बढ़ाने की मांग को लेकर करेंगे प्रदर्शन

हलधर किसान, भोपाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गई है। किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी और सोयाबीन का भाव 6 हजार रुपये करने की मांग को लेकर कांग्रेस हर जिले में 'किसान न्याय यात्रा' निकालने जा रही ही है। इसका आगाज 10 सितंबर को मंदसौर जिले के गरोठ से किया जाएगा।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार किसानों की आमदनी पर वार कर रही है। किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश के हर जिले में किसान न्याय यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस 20 सितंबर को फसलों के एमएसपी बढ़ाने की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी। किसान न्याय यात्राश् के तहत उस दिन सभी 55 जिलों के कलेक्टर कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस इस मांग और किसानों के साथ हो रहे अन्याय को मुखरता से उठाएगी। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए जीतू पटवारी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं, लेकिन किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार किसानों से सोयाबीन 6,000 रुपये प्रति क्विंटलए गेहूं 2,700 रुपये प्रति क्विंटल और धान 3,100 रुपये प्रति क्विंटल खरीदे। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में गेहूं के लिए 2700 रुपये और धान के लिए 3100 रुपये एमएसपी देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद भाजपा यह वादा भूल गई।

पटवारी ने आरोप लगाया कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते 5 सितम्बर को मध्य प्रदेश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। कृषि मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि प्राइस सपोर्ट स्कीम के माध्यम से सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी। मगर मध्य प्रदेश को इस योजना से बाहर रखा गया है। प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए किसानों के हितों पर कुठाराघात किया गया है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का भाव लगभग 4000 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया है। जबकि समर्थन मूल्य 4892 रुपये प्रति क्विंटल है जो नाकाफी है।

एजेंसी देना है-

प्रतिष्ठित मासिक समाचार पत्र हलधर किसान/ इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म किसान प्लस टीवी पर कृषि क्षेत्र से जुड़े शोध, अनुसंधान, नई तकनिक, योजनाओं के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के समावेश के साथ नियमित रुप से प्रकाशित हो रहा है।

अगर आप भी कृषि पत्रकारिता में रूचि रखते है तो हमारे न्यूज चैनल सहित अखबार से जुड़ने के लिए हमारे वाट्सअप नंबर(88174 02860) या हमारे प्रधान कार्यालय 598, वेगॉस मॉल, कार्पोरेट बिल्डिंग, एस.14 द्वारका साउथ वेस्ट, नई दिल्ली 110075 या मप्र में 762, बीज भंडार भवन, न्यू नूतन नगर खरगोन में संपर्क कर सकते है।

खरीफ फसल की बुआई 1065 लाख हेक्टेयर से ज्यादा

हलधर किसान

धान, दलहन और मोटे अनाज का बढ़ा रकबा

नई दिल्ली। इस साल खरीफ फसलों की बुआई में पिछले साल की तुलना में 1.93 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुसार 27 अगस्त 2024 तक खरीफ फसलों का कुल बुआई क्षेत्र 1065.08 लाख हेक्टेयर हो गया है, जबकि वर्ष 2023 में इस समय तक यह क्षेत्र 1044.85 लाख हेक्टेयर था। इस वर्ष विशेष रूप से धान, दलहन और मोटे अनाज की बुआई में वृद्धि देखी गई है।

दलहन की बुआई में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। दलहन की बुआई का क्षेत्र 5.72 फीसदी बढ़कर 122.16 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो वर्ष 2023 में 115.55 लाख हेक्टेयर था। दालों में अरहर और मूंग की बुआई में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, जबकि उड़द की बुआई पिछली साल की तुलना में पिछड़ी है। अरहर की बुआई 45.78 लाख हेक्टेयर और मूंग की बुआई 34.07 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। वहीं, उड़द की बुआई 29.04 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले साल के 30.81 लाख हेक्टेयर से कम है।

धान की बुआई में 4.24 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है। अब तक 394.28 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई हो चुकी है, जो वर्ष 2023 में इस समय तक 369.05 लाख हेक्टेयर थी। मोटे अनाज की बुआई 4.51 फीसदी बढ़कर 185.51 लाख हेक्टेयर हो गई है, जबकि वर्ष 2023 में यह क्षेत्र 177.50 लाख हेक्टेयर था। इसमें मक्का की बुआई 87.23 लाख हेक्टेयरए ज्वार की 14.93 लाख हेक्टेयर, बाजरा की 68.85 लाख हेक्टेयर और रागी की 9.17 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। मोटे अनाज में सिर्फ बाजरा की बुआई पिछड़ी है, जो पिछले साल से कम है।

तिलहन की बुआई में भी 0.83 फीसदी की मामूली वृद्धि हुई है। इसमें मूंगफली की बुआई 46.82 लाख हेक्टेयर, सोयाबीन की बुआई 125.11 लाख हेक्टेयर, सूरजमुखी की बुआई 0.71 लाख हेक्टेयर और तोल की बुआई 10.67 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है।

गन्ने का रकबे हल्की बढ़त के साथ उसका बुआई कुल क्षेत्रफल 57.68 लाख हेक्टेयर हो गया है। वहीं, कपास की बुआई में 11.36 फीसदी की गिरावट आई है, जिससे यह क्षेत्र 2023 के 111.39 लाख हेक्टेयर से घटकर 2024 में 122.74 लाख हेक्टेयर रह गया है।

जूट और मेस्टा की बुआई भी 5.70 लाख हेक्टेयर तक सिमट गई है, जो पिछले साल की तुलना में कम है।कुल मिलाकर, इस साल खरीफ फसलों की बुआई में धान, दलहन और मोटे अनाज में बढ़त के साथ अच्छी प्रगति हुई है, लेकिन कुछ फसलों में गिरावट भी दर्ज की गई है।

7.12 फीसदी बढ़ा कोयला उत्पादन, सालाना स्टॉक में 36.2 प्रतिशत की वृद्धि

हलधर किसान (खनिज) नई दिल्ली। कोयला मंत्रालय ने 25 अगस्त तक कोयले के समग्र उत्पादन में वृद्धि हासिल की है। वित्त वर्ष 2024.25 के लिए संचयी कोयला उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि होने से यह 370.67 मिलियन टन हो गया है जो वित्त वर्ष 2023.24 की इसी अवधि में हुए 346.02 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 7.12 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

इसके अलावा कोयले की कुल आवाजाही में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो वित्त वर्ष 2024.25 के लिए 25 अगस्त 2024 तक 397.06 मिलियन टन तक पहुंच गई है। यह पिछले वर्ष के 376.44 मिलियन टन आवाजाही की तुलना में 5.48 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर को दर्शाती है।

बिजली क्षेत्र को कोयले के प्रेषण के संदर्भ में, वित्त वर्ष 2024.25 के लिए 25 अगस्त 2024 तक संचयी उपलब्धि 325.97 मिलियन टन है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 313.44 मिलियन टन थी। यह वृद्धि 01.04.2024 के अनुसार टीपीपी में 47 मिलियन टन के विशाल शुरुआती भंडारण के बावजूद हासिल की गई है। यह बिजली क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयले की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

खानों, टीपीपी और पारगमन में सिरहेड्स सहित कोयले के कुल स्टॉक की स्थिति 25 अगस्त 2024 तक 121.57 मिलियन टन तक पहुंच गई। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के 89.28 मिलियन टन के स्टॉक की तुलना में 36.2 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, 25 अगस्त, 2024 तक ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) में कोयले का स्टॉक 37.55 मिलियन टन है, जबकि पिछले वर्ष यह 29.47 मिलियन टन था, जो लगभग 27.41 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।कोयला स्टॉक की यह उच्च स्थिति कोयला मंत्रालय की कोयले की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उत्पादन, प्रेषण और स्टॉक स्तरों में निरंतर वृद्धि, देश के ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों का समर्थन करते हुए एक विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के बारे में मंत्रालय के प्रयासों को दर्शाती है।

कृषि क्षेत्र में14 हजार करोड़ खर्च करेगी सरकार मोदी केबिनेट ने 7 योजनाओं को दी मंजूरी

हलधर किसान, नई दिल्ली।

केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र को काफी तवज्जो दे रही है। इस क्षेत्र की जीडीपी और रोजगार पैदा करने में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र से जुड़ी सात बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है, जिन पर सरकार करीब 14,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इनमें से 2,817 करोड़ रुपये का डिजिटल कृषि मिशन के लिए दिए जाएंगे। वहीं, फसल विज्ञान पर 3,979 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन फैसलों को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। उन्होंने कहा कि कृषि शिक्षा और प्रबंधन को बेहतर करने के लिए 2291 करोड़ रुपये के प्रोग्राम को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि पशुधन के स्थायी स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपये के प्लान को मंजूरी दी गई है। सरकार का फोकस बागवानी पर भी है। उसने बागवानी के सतत विकास के लिए 860 करोड़ रुपये की एक बड़ी योजना मंजूरी दी है। साथ हीए कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने पर 1,202 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित योजना पर 1,115 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सभी सातों योजनाओं के लिए कुल 13,960 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है।

इन योजनाओं पर खर्च होगी राशि

1. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन

डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2817 करोड़ रुपए की मदद से बनेगाए इसके दो फाउंडेशन स्टोन रहेंगे. एग्री स्टैक और कृषि डिसिशन सपोर्ट सिस्टम, एग्री स्टैक में बेसिक डेटा रहेगा और कृषि डिसिशन सपोर्ट सिस्टम में उपलब्धता का डेटा रहेगा, जो सैटेलाइट से डेटा आता है, वो भी इसी में होगा। इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा।

2. फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी

कैबिनेट ने दूसरा फैसला क्रॉप साइंस के लिए फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी से जुड़ा लिया है। इसकी मदद से किसानों को 2047 तक क्लाइमेट रेजिलिएंस और फूड सिक्योरिटी के लिए तैयार करना है। इस प्रोग्राम में 6 पिलर्स रखे गए हैं। इसका खर्च 3979 करोड़ रुपए है। इसमें रिसर्च और एजुकेशन में बहुत जोर दिया जाएगा।

3. एग्रीकल्चर एजुकेशन, मैनेजमेंट और सोशल साइंस

कैबिनेट ने एग्रीकल्चर एजुकेशनए मैनेजमेंट और सोशल साइंस को मजबूत करने के लिए भी फैसला लिया है। इसके लिए 2291 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इसमें सारा काम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से किया जाएगा। इसके तहत क्लाइमेट रेजिलिएंस और नेचुरल फार्मिंग को कोर्स में शामिल किया जाएगा।

4. सस्टेनेबल लाइवस्टॉक हेल्थ और प्रोडक्शन

किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए लाइवस्टॉक की हेल्थ और इसके प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें डेयरी प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर काम होगा। इसके लिए 1702 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

5. सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर

हॉर्टिकल्चर में सब्जियां है, फ्रूटस, मशरूम है और कई तरह के प्लांट्स हैं। इसके लिए 860 करोड़ रुपए का लेआउट है। इससे किसानों की इनकम बढ़ने का स्कोप बढ़ जाएगा।

6. कृषि विज्ञान केंद्र

इसके तहत कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत किया जाएगा। किसानों के साथ कैसे जुड़ा जाए और उन्हें स्वावलंबी बनाया जाए, इसके लिए ये प्रोग्राम है। इसके लिए 1202 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

7. नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट

रिजरवॉयर, ग्राउंड वॉटर और बाकी नेचुरल रिसोर्स को कैसे अच्छे से मैनेज किया जाएए इसके लिए 1115 करोड़ रुपए का प्लान है।

भारतीय कृषि का अमृतकाल

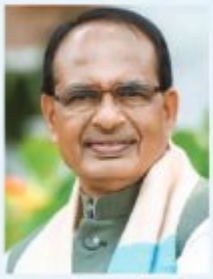

कृषि विकास और किसान कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अन्न के माध्यम से हमारे जीवन संचालन के सूत्रधार अन्नदाता के जीवन में सुख.समृद्धि लाना हमारा संकल्प है। इस संकल्प की पूर्ति के लिए हम हरसंभव प्रयास करेंगे। किसान की आय बढ़ाने के लिए हमने 6 सूत्री रणनीति बनाई है। उत्पादन बढ़ानाए खेती की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम दिलाना, प्राकृतिक आपदा में राहत की उचित राशि दिलाना, कृषि का विविधीकरण तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना इसके अहम पहलू हैं। उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने के लिए सबसे जरूरी है अच्छे बीज, जो कम पानी और विपरीत मौसम में भी बेहतर उत्पादन में सक्षम हो सकें। ऐसे बीजों की 109 नई किस्में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने राष्ट्र और किसानों को समर्पित की हैं।

बीते 10 वर्षों में कृषि परिदृश्य तेजी से बदला है। ग्लोबल वार्मिंग तथा पर्यावरण असंतुलन जैसी समस्याओं के बीच उत्पादकता बढ़ाने की चुनौती खड़ी हो गई है। इस चुनौती से निपटने के लिए अगले 5 वर्षों में हमारा लक्ष्य जलवायु अनुकूल फसलों की 1500 नई किस्में तैयार करने का है। वर्तमान में विज्ञान से ही किसानों का कल्याण संभव है। मुझे अपने कृषि विज्ञानियों पर गर्व है, जो जलवायु अनुकूल किस्में तैयार कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कृषि में किए जा रहे नवाचारों से कृषि एवं किसान कल्याण सुनिश्चित होगा।

किसान होने के नाते मैं भलीभांति समझता हूं कि बढ़िया उत्पादन के लिए अच्छे बीज कितने आवश्यक हैं। अगर बीज उन्नत और मिट्टी एवं मौसम की प्रकृति के अनुकूल होंगे तो उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। मोदी जी ने यह समझा और व्यापक विजन के साथ इस दिशा में कार्य करने के लिए मार्गदर्शित किया। विविधता भारतीय कृषि की विशेषता है। यहां कुछ दूरी के अंतराल पर ही खेती का मिजाज बदल जाता है, जैसे मैदानी खेती अलग है तो पहाड़ों की खेती अलग। इन सभी भिन्नताओं और विविधताओं को ध्यान में रखते हुए फसलों की 109 नई किस्में जारी की गई हैं। इनमें खेती की 69 किस्में और बागवानी की 40 किस्में राष्ट्र को समर्पित कर दी गई हैं। भारत को ग्लोबल न्यूट्रिशन हब बनाने और श्रीअन्न को प्रोत्साहित करने के लिए मोदी सरकार पूरी तरह संकल्पबद्ध है। हमारा संकल्प है कि किसान के परिश्रम का उचित मूल्यांकन हो और उन्हें फसलों का उचित दाम मिलेए इसके लिए हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कर रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाना हमारी प्राथमिकता में है और उत्पादन बढ़ाने के साथ.साथ भारत की चिंता भी रही है कि मानव शरीर और मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित उत्पादन हो। आज भारत नई हरित क्रांति का साक्षी बन रहा है। हमारे अन्नदाता ऊर्जादाता तथा ईंधनदाता भी बन रहे हैं। मोदी जी के प्रयासों से खेती के साथ ही पशुपालन, मधुमक्खी पालन, औषधीय खेती, फूलों.फलों की खेती सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों को सशक्त बनाया जा रहा है।

संपादकीय

पूर्ववर्ती सरकारों की प्राथमिकता में कृषि और किसान रहे ही नहीं, जबकि मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। वर्ष 2013.14 में कृषि मंत्रालय का बजट 27,663 करोड़ रुपए था, जो 2024.25 में बढ़कर 1,32,470 करोड़ रुपए हो गया है। यह बजट सिर्फकृषि विभाग का है। कृषि से संबद्ध क्षेत्रों और फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए अलग बजट है। मोदी सरकार किसानों को यूरिया और डीएपी सस्ती दरों पर उपलब्ध करा रही है। यूरिया पर सरकार किसानों को करीब 2,100 रुपए जबकि डीएपी के एक बैग पर 1083 रुपए की सब्सिडी दे रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसान स्वावलंबी और सशक्त हुआ है। फसलों के नुकसान पर भी फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है।

मोदी सरकार ने किसान को सशक्त बनाने के लिए बीज से लेकर बाजार तक हर वह फैसला लियाए जो किसानों के लिए खेती को और आसान बनाए। उनकी मुश्किलें कम करे और मुनाफा बढ़ाए। इसी कड़ी में एक लाख करोड़ रुपए के एग्री इन्फ्राफंड के जरिए कृषि से जुड़ा बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है। पूरे देश में 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र किसान और विज्ञान को जोड़ रहे हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना के जरिए टैक्नोलाजी से दूरदराज की हमारी माताओं.बहनों को भी जोड़ा जा रहा है। कृषि सखियों को प्रशिक्षण देने के पहले चरण में अब तक 35,000 कृषि सखियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। मोदी जी का विजन है कि भारत कृषि में आत्मनिर्भर बने। इस दिशा में भी रणनीति बनाकर कार्य किया जा रहा है। अगले 5 वर्षों में हम 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 100 निर्यात केंद्रित बागवानी क्लस्टर बनाएंगे। किसानों के लिए मंडी तक पहुंच बेहतर बनाने के लिए 1500 से अधिक मंडियों का एकीकरण किया जाएगा। साथ ही 6,800 करोड़ रुपए की लागत से तिलहन मिशन की शुरुआत कर रहे हैं। सब्जी उत्पादन क्लस्टर बनाने की भी तैयारी है। इससे छोटे किसानों को सब्जियों.फलों और अन्य उपजों के लिए नए बाजार और बेहतर दाम मिलेंगे। सरकार ने यह संकल्प भी लिया है कि दलहन फसलों में तुअरए उड़द और मसूर की पूरी खरीद एमएसपी पर की जाएगी। यजुर्वेद में उल्लिखित है 'अन्नानां पतये नमः क्षेत्राणां पतये नमः' अर्थात अन्न के स्वामी और खेतों के स्वामी अन्नदाताओं को नमन। कृषि पराशर में भी उल्लेख है, अन्न ही प्राण है, अन्न ही बल है एवं अन्न ही समस्त प्रयोजनों का साधन है। किसानों के बिना इस देश का अस्तित्व ही अधूरा है। इसलिए हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी किसानों को प्रणाम किया गया है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसका आत्मा। हमारे लिए किसान की सेवा भगवान की पूजा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के दीर्घकालिक विजन तथा सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी, समावेशी और समग्र विकास वाली सोच के साथ भारत एवं भारतीय कृषि निरंतर आगे बढ़ रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे किसान भाई.बहन आजादी के अमृतकाल में आत्मनिर्भर भी बनेंगे और समृद्ध संपन्न होने के साथ.साथ देश के अन्न भंडार भरते रहेंगे।

.सौजन्य :. लेखक श्री शिवराज सिंह चौहान , केंद्रिय मंत्री भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

पितृ पक्ष में श्राद्ध की 16 तिथियों का क्या है महत्व

हलधर किसान

अजमेर (ज्योतिष). सनातन धर्म में पितृ पक्ष की अवधि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस अवधि में पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण और पिंडदान आदि करने का विधान है। माना जाता है कि इससे उन्हें तृप्ति मिलती है और वह हमें सुख.समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं।

पितृ पक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होती है और यह आश्विन माह की अमावस्या तिथि तक चलती है। इस बार पितृ पक्ष 17 सितंबर 2024 से शुरू हो रहे हैं, जो 02 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। इस दौरान लोग अपने पितरों के निमित्त आश्विन कृष्ण पक्ष में तर्पण और श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। पितृ पक्ष लगभग 15 दिन की अवधि होती है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को भोजन व अर्पण आदि कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। माना जाता है कि इस समय पितृ, पितृलोक से धरती पर आते हैं। देखा जाए तो यह पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए एक उत्तम समय माना गया है। वहीं अगर कोई व्यक्ति पितृ दोष से परेशान है, तो पितृ पक्ष में वह इससे छुटकारा पाने के उपाय भी कर सकता है, जो लाभकारी साबित होते हैं।

पितृ पक्ष के दौरान कई तरह के नियमों का ध्यान रखना जरूरी होता है। साथ ही इस दौरान कई कार्यों को करने की मनाही भी होती है। नए कपड़े, वाहन, जमीन आदि खरीदना और शुभ कार्य जैसे विवाह, सगाई, मुंडन, उपनयन संस्कार आदि करना वर्जित माना जाता है। इस दौरान व्यक्ति को तामसिक भोजन से भी दूरी बनाने की सलाह दी जाती है। साथ ही इस अवधि में किसी भी तरह के नए बिजनेस की शुरुआत करना भी शुभ नहीं माना जाता।।

इन चीजों के बिना अधूरा है श्राद्ध कर्म

सिंदूर, रोली, सुपारी, रक्षा सूत्र, कपूर, जनेऊ, हल्दी, घी, शहद, काला तिल, तुलसी और पान के पत्ते, जौ, गुड़, दीया, अगरबत्ती, दही, गंगाजल, केला, सफेद फूल, उड़द दाल, मूंग और ईख, कुशा, धुर्वा, गाय का कच्चा दूध, आदि चीजें। पितृ पक्ष के दौरान पितरों का तर्पण करना बेहद शुभ माना जाता है। तर्पण के लिए कुश, अक्षत, जौ और काले तिल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद प्रार्थना मंत्र का जाप करें। फिर आशीर्वाद लेते हुए प्रार्थना करें। तर्पण के दौरान पूर्व दिशा की ओर मुख रखें। पहले जौ और कुश से ऋषियों के लिए तर्पण करें। इसके बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके जौ और कुश से मानव तर्पण करें। अंत में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल और कुश से पितरों का तर्पण करें।

इस दिन से हो रही है शुरुआत

17 सितंबर मंगलवार . प्रोष्ठपदी पूर्णिमा श्राद्ध
18 सितंबर बुधवार . प्रतिपदा का श्राद्ध
19 सितंबर गुरुवार . द्वितीया का श्राद्ध
20 सितंबर शुक्रवार . तृतीया का श्राद्ध
21 सितंबर शनिवार . चतुर्थी का श्राद्ध
22 सितंबर रविवार . पंचमी का श्राद्ध
23 सितंबर सोमवार . षष्ठी का श्राद्ध और सप्तमी का श्राद्ध
24 सितंबर मंगलवार . अष्टमी का श्राद्ध
25 सितंबर बुधवार . नवमी का श्राद्ध
26 सितंबर गुरुवार . दशमी का श्राद्ध
27 सितंबर शुक्रवार . एकादशी का श्राद्ध
29 सितंबर रविवार . द्वादशी का श्राद्ध
30 सितंबर सोमवार . त्रयोदशी का श्राद्ध
01 अक्टूबर मंगलवार . चतुर्दशी का श्राद्ध
02 अक्टूबर बुधवार . सर्व पितृ अमावस्या

वर्ग पहेली-5

बाएं से दाएं

1. किस्मत वाला (4)
5 पूर्व दिशा में बहुत दूर (5)
6. कृष्णभक्ति के प्रवर्तक बंगाली कवि (4)
8. बहुत बड़ा हिस्सा (4)
10. दूल्हे का जलूस (3)
12. बहना पिघलना (3)
14. छोटा तालाब (4)
16. दया करने योग्य (4)
18.राज्याभिषेक (5)
19. सामूहिक (4)

ऊपर से नीचे

1. भगवान शिव, भगवान गणेश (4)
2. सरस्वती (3)
3. श्रेष्ठ पुरुष (5)
4. श्रमजीवी (4)
7. सपाट (4)
9. देशी माह भादों (4)
11. राजनीति संबंधी (5)
13. देवताओं के राजा इंद्र (4)
15. दोष, प्रमाद, भूल आदि के मार्जन हेतु किया जाने वाला कर्म, शोधन (4)
17. अनाथ (3)

१		२		■	■	३	■	४
	■		■	५				
६			७	■	■		■	
	■	■	८		९		■	
■	१०	११		■	१२			■
१३	■	१४				■	■	१५
	■		■	■	१६	१७		
१८					■		■	
	■		■	■	१९			

वर्ग पहेली 4 का सही उत्तर

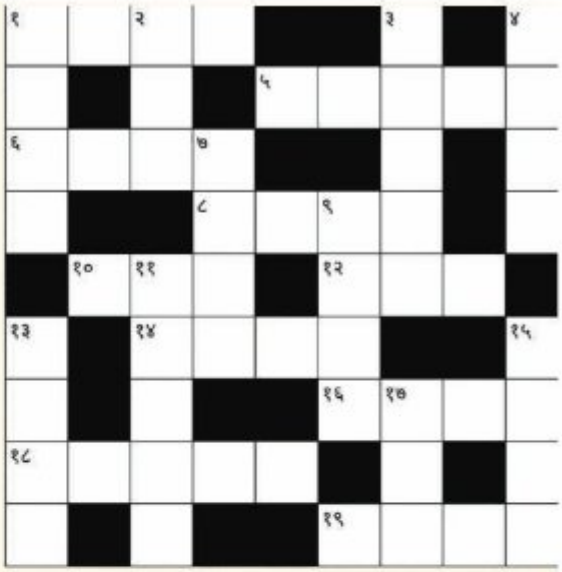

१ क	न	२ कौ	वा	■	■	३ सा	■	४ का
न	■	श	■	५ मं	ग	ल	वा	र
६ प	द्मा	ल	७ य	■	■	गि	■	खा
टी	■	■	८ का	लां	९ त	र	■	ना
■	१० अ	११ ज	य	■	१२ रे	ह	न	■
१३ म	■	१४ ना	क	दा	र	■	■	१५ म
मा	■	न	■	■	१६ ना	१७ ग	रि	क
१८ न	र	खा	द	क	■	द्दा	■	रं
त	■	ना	■	■	१९ अ	र	विं	द

ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसदों, विधायकों, उद्योगपति

'देश के किसानों के लिए मजबुत और संगठित ताकत है आपका संगठन : श्रीमति ईरानी

हलधर किसान

नई दिल्ली। देश के किसान के लिए संगठित ताकत आप लोग हैं और आपका मंच नेताओं को तलाशना चाहिए ना कि आपको किसी नेता या अधिकारी के पास जाना चाहिए। उसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि आपकी सदस्यता प्रमाणित होनी चाहिए। इसलिए आप अपने संगठन के सदस्यों की संख्या प्रमाणित करके रखें एवं आपके जो भी मुद्दे हैं, उन्हें प्रमाण सहित हमारे सामने लाईये हम जेपी नड्डाजी से जल्द से जल्द आपकी मुलाकात करवा कर इन समस्याओं का स्थाई समाधान करने की पुरजोर प्रयास करेंगे।

उक्त बात ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन की नई दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के हाल में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में बतौर अतिथि पहुंची पूर्व केंद्रिय मंत्री स्मृति ईरानी ने कही। उन्होंने बैठक के दौरान श्रीमति ईरानी के सामने संगठन पदाधिकारियों द्वारा रखी गई, मांगों और समस्याओं के निराकरण में हरसम्भव मदद का आश्वासन दिया।

संगठन की राष्ट्रीय बैठक में कैट के राष्ट्रीय महासचिव चांदनी चौक नई दिल्ली के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि लगभग 35 वर्ष पूर्व अटल बिहारी वाजपेई के आव्हान पर व्यापारियों के एक राष्ट्रीय संगठन कैट का गठन किया गया था और हमारा यह मानना है कि 'सड़क हमारा अंतिम हथियार होना चाहिए' उसके पहले जितनी कोशिश हो पूरी करनी चाहिए और कैट ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी समस्याओं के समाधान का पूर्ण रूप से प्रयास करेगी। बैठक में देश के कई नेताओं एवं अधिकारियों ने उपस्थित होकर संगठन के सदस्यों की समस्याओं को विभिन्न माध्यमों से हल करवाने का आश्वासन दिया।

'ज्वाइंट सेक्रेटरी प्लांट प्रोटक्शन मुकानंद अग्रवाल के समक्ष संगठन के राष्ट्रीय 'सचिव अरविंद भाई पटेल' ने पेस्टिसाइड से संबंधित समस्त समस्याओं को उनके समक्ष रखा। श्री अग्रवाल ने सदस्यों की समस्याओं को गंभीरता से सुना समझा। उन्होंने बताया कि हाल ही में

पूर्व वित्त राज्य मंत्री कराड, सांसद खंडेलवाल एवं राज्यसभा सांसद श्री बाबूराव ने भी दिया संगठन की समस्याओं के निराकरण का आश्वासन

इस पद पर नियुक्त किए हैं, इस समस्याओं को समझने के लिए कुछ समय चाहिए, जल्द ही इन सब बातों का उचित निराकरण किया जाएगा।

जनप्रतिनिधियों के साथ कृषि मंत्री से करेंगे मुलाकात

दूसरे सत्र में 'हैदराबाद से राज्यसभा के सांसद जी बाबूराव ने व्यापारियों के आश्वासन दिया कि वह आपकी समस्याओं के लिए जे पी नड्डा एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करके इन्हें हल करवाने का प्रयास करेंगे।

पेस्टिसाइड मैन्यु फार्म्युलेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एग्रोकेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफइंडियाए क्रॉप लाइफ इंडिया के पदाधिकारी के रूप में दीपक शाह, पीजे सुरेश, डॉ आरती कुमारी, धानुका ग्रुप के चेयरमैन आरजी अग्रवाल, फेडरेशन ऑफसीड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के एवं नेशनल सीड एसोसिएशन के राघवन, बीबी पटनायक, डॉक्टर दीपंकर पांडे, मासा महाराष्ट्र के अध्यक्ष श्रीरामनाके, महिको सीड के संजय देशपांडे एवं इंडियन पोटाश लिमिटेड के जीएम भूएन सिंह ने भी संगठन के सदस्यों की समस्याओं को समझा एवं उनके निराकरण का आश्वासन दिया।

खाद बीज एवं कीटनाशक की समस्याओं का हो स्थाई हल

एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री ने बताया कि भारत को दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में हमारे व्यापारियों का भी अहम योगदान है। राष्ट्रीय बैठक में संगठन से जुड़े कर्नाटक, आंध्र तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित अन्य कई प्रांतों के पदाधिकारियों ने शामिल होकर संगठन की एकता का परिचय दिया। संगठन की

इसी ताकत से केंद्र सहित प्रदेश सरकारें खाद, बीज व्यापारियों से जुड़ी समस्याओं को संगठन के आव्हान पर सुनने के साथ ही उनके निराकरण का प्रयास करती है। संगठन के सदस्य पिछले कई वर्षों से खाद-बीज एवं कीटनाशक की अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, शासन, प्रशासन से भी लगातार ज्ञापन, पत्राचार के माध्यम से आवेदन, निवेदन किया जा रहा है, जिनका स्थाई हल किया जाना अनिवार्य है। इस अवसर पर कैट के राष्ट्रीय महामंत्री शंकर भाई ठक्कर, मुंबई के अविनाश निमोनकर, राजस्थान के मनोज गोयल आदि भी उपस्थित थे।

उठा टैगिंग एवं फार का मुद्दा

संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने 'शिर्डी के सांसद भाऊ साहब वाकचौरे के नेतृत्व में सेक्रेटरी फर्टिलाइजर के साथ मुलाकात करते हुए उन्हें अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन दिया जिसमें 'टैगिंग एवं फार का मुद्दा उठाया। सेक्रेटरी फर्टिलाइजर ने आश्वासन दिया है कि वे इस बारे में जल्द से जल्द अधिकारियों एवं कंपनी प्रतिनिधियों के साथ बात करके निराकरण का प्रयास करेंगे।

संगठनों का किया सम्मान

इस सम्मेलन के दौरान गुजरात में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन संपन्न करने पर गुजरात इकाई का, महाराष्ट्र में मकोका के विरोध में प्रदेश स्तरीय आंदोलन कर उसे वापस लेने पर महाराष्ट्र संगठन, रायगढ़ द्वारा मासिक पत्रिका शुरू करने पर राजस्थान के संगठन, बिहार में एक्सपायरी मटेरियल वापसी के लिए आदेश जारी करवाने के लिए बिहार संगठन एवं उत्तर प्रदेश में पिछले 3 सालों की खरीदी बिक्री के आदेश को रुकवाने के लिए यूपी के संगठन का ऑल इंडिया संगठन की ओर से सम्मान किया गया।

देशभर के पदाधिकारी हुए शामिल

इस बैठक में राष्ट्रीय महासचिव 'प्रवीण भाई पटेल, विशेष सलाहकार सत्यनारायण कासट, कोषाध्यक्ष आभासाहेब भोकरे, राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय रघुवंशी, अरविंद भाई पटेल, पुरुषोत्तम खंडेलवाल व मध्य प्रदेश के कृषि आदान विक्रेता संघ के अध्यक्ष मानसिंह राजपूत, सुरेंद्र सिंह बेरीवाल, सरदार हरमेश सिंह, अतुल त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश संघ के अध्यक्ष नागी रेड्डी, अतुल मुंद्रा, राकेश आहूजा, सुभाष दरक, अशोक मारू, एडवोकेट सरदाना, प्रमोद शर्मा, मधुकर मामडे, अशोक रेड्डी, राजेश मलैया सुभाष दाक, प्रमोद शर्मा, नरेश गोयल, हरमेश सिंह, वीरेंद्र कपूर, सुरेंद्र सिंह बेरीवाला, आबा साहेब भोकरे, मनमोहन सरावगी, राज एसोवाट, एम सत्यमूर्ति, एम मोहन, वी वी नागीरेड्डी, बसवराज, एम बालेश, राजेश मलैया, देवेंद्र वर्मा, अतुल त्रिपाठी, अतुल मुंदड़, द्वारिका गुप्ता सहित राष्ट्रीय बैठक में संगठन से जुड़े कर्नाटक, आंध्र तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित अन्य कई प्रांतों के पदाधिकारियों ने शामिल होकर संगठन की एकता का परिचय दिया। संचालन राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय रघुवंशी ने किया एवं आभार प्रदर्शन राकेश आहूजा हिमाचल ने किया।

राष्ट्रीय बैठक से प्रदेश और जिलास्तर के व्यापार को मिलेगा बढ़ावा

राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में कृषि आदान विक्रेताओं के संबंध में हुए विचार, विमर्श और चिंतन से जो निष्कर्ष निकला है, उससे निश्चित ही राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर तक के व्यापारियों को राहत मिलेगी। यह बात जागरुक कृषि आदान विक्रेता संघ के जिलाध्यक्ष श्रीकृष्णा दुबे ने हलधर किसान से विशेष चर्चा में कही। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कलंत्री, प्रवक्ता संजय रघुवंशी सहित अन्य पदाधिकारियों को साधुवाद जिन्होंने बैठक में न केवल देशभर के पदाधिकारियों बल्कि राष्ट्रीय स्तर के जनप्रतिनिधियों, पूर्व मंत्रियों, सांसदों को आमंत्रित कर उनके समक्ष संगठन के माध्यम से व्यापारियों की समस्याएं, शिकायतें रखी, जिसका निराकरण होने पर संगठन के साथ व्यापारियों को मजबूती मिलेगी। यह संगठन कि शक्ति का प्रभाव है, जो राष्ट्रीय स्तर पर ब्लॉक, जिले और प्रदेश के व्यापारियों की बात रखी गई। श्री दुबे ने बताया कि कृषि का क्षेत्र हमारे देश की बड़ी आबादी को कवर करने के साथ ही रोजगार भी प्रदान करता है। ऐसे में इस व्यापारी से जुड़े खाद, बीज व्यापारी भी कहीं न कहीं गांवों व कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे है। राष्ट्रीय बैठक में जिस तरह शिरडी महाराष्ट्र के सांसद भाऊसाहेब वाकचौरे, पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा राज्यसभा सांसद भागवत कराड, जॉइंट सेक्रेटरी प्लांट प्रोटक्शन कृषि मंत्रालय नई दिल्ली मुकानंद अग्रवाल, दिल्ली चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल, पूर्व मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने कार्यक्रम में शामिल होकर संगठन को सम्मान दिया और संगठन के माध्यम से समस्याओं के हल का आश्वासन दिया है, इससे समूचे देश के व्यापारियों को राहत मिलेगी।

सोलर एनर्जी में देश ने बनाया रिकार्ड

पिछले 6 माह में देश ने रिकॉर्ड 15 गीगावाट सौर क्षमता जोड़ी: रिपोर्ट

हलधर किसान

नई दिल्ली। भारत ने 2024 की पहली छमाही में लगभग 15 गीगावाट की रिकॉर्ड सोलर इंस्टालेशन दर्ज की है। अमेरिकी एजेंसी मर्कम कैपिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार यह वृद्धि पहले से स्थापित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए डेवलपर्स की तेजी से की गई कोशिशों के कारण हुई। इस अवधि के दौरान सोलर कैपेसिटी में 2023 के पहले चरण की तुलना में 282 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जनवरी से जून 2023 के बीच भारत ने 3.89 गीगावाट की सोलर क्षमता जोड़ी थी, जबकि 2024 की पहली छमाही में यह आंकड़ा तेजी से बढ़कर 15 गीगावाट पहुंच गया जो कि अब तक के सभी रिकॉर्ड को पार करता है। जून 2024 तक भारत की कुल स्थापित सोलर क्षमता 87.2 गीगावाट तक पहुंच गई, जिसमें लगभग 87 प्रतिशत यूनिट-स्केल परियोजनाओं से और 13 प्रतिशत रूफटॉप सोलर सिस्टम से आई है। सोलर ऊर्जा अब भारत की कुल स्थापित पावर क्षमता का 19.5 प्रतिशत और कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का 44 प्रतिशत बनाती है।

सोलर एनर्जी पर सरकार का फोकस

टेक्नोलॉजी के इस दौर में हमें अपने चारों तरफ कई नई टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती हैं। इन्हीं टेक्नोलॉजी में एक टेक्नोलॉजी ऐसी भी है, जो इस समय की सबसे बड़ी मांग है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी पर सरकार का फोकस है। इसके फायदे के साथ ही कमाई के भी बड़े मौके हैं। सोलर पैनल को आप कहीं भी इंस्टॉल करा सकते हैं। बिजली के भारी भरकम बिल की टेंशन भी खत्म हो सकती है।

दरअसल, सोलर पैनल लगाने वालों को केंद्र सरकार का न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय रूफटॉप सोलर प्लांट पर 30 फीसदी सब्सिडी देता है। बिना सब्सिडी के रूफटॉप सोलर पैनल लगाने पर करीब 1 लाख रुपए का खर्च आता है। एक सोलर पैनल की कीमत तकरीबन एक लाख रुपए है। राज्यों के हिसाब से वह खर्च अलग होगा। सब्सिडी के बाद एक किलोवॉट का सोलर प्लांट मात्र 60 से 70 हजार रुपए में कहीं भी इंस्टॉल करा सकते हैं। वहीं, कुछ राज्य इसके लिए अलग से अतिरिक्त सब्सिडी भी देते हैं।

रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर सोलर परियोजनाओं की औसत लागत में 26 प्रतिशत की गिरावट और तिमाही आधार पर 2 प्रतिशत की कमी को दर्ज किया गया है। मर्कम कैपिटल ग्रुप के सीईओ राज प्रभु ने कहा कि 2024 भारत की सोलर इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हो रहा है जिसमें पहली छमाही में शानदार प्रदर्शन देखा गया है।

हालांकि परियोजना समय पर पूरा करने और 2030 तक 280 गीगावॉट के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मटक आपूर्ति और ग्रिड कनेक्टिविटी से संबंधित चुनौतियों को तत्काल हल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। 2024 की पहली छमाही में कुल 41.4 GW की टेंडर जारी की गई जो 2023 की पहली छमाही की तुलना में 51 प्रतिशत अधिक है। इसके अतिरिक्त लगभग 31.8 गीगावाट की परियोजनाओं की नीलामी की गई जो 2023 की पहली छमाही की तुलना में 321 प्रतिशत अधिक है।

कृषि व्यापार बेहतरी के लिए शिर्डी सांसद ने केंद्रिय कृषि मंत्री को लिखा पत्र

हलधर किसान, इंदौर (श्रीकृष्णा दुबे)।

कृषि इनपुट डीलरों के सामने आने वाली चुनौतियों और परिचालन संबंधी समस्याओं पर महाराष्ट्र के शिर्डी संसदीय क्षेत्र के सांसद भाऊसाहेब वाकचौरे ने चिंता जताते हुए केंद्रिय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। यह पत्र सांसद वाकचौरे ने दिल्ली में आयोजित कृषि आदान विक्रेता संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के दौरान एसोसिएशन द्वारा सांसद वाकचौरे के सामने उठाई गई मांगों पर विचार कर लिखा है। सांसद वाकचौरे ने कृषि मंत्री को लिखे पत्र में चार प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला है और इन मुद्दों को जल्द से जल्द हल किए जाने की मांग की है।

कृषि समुदाय की बेहतरी के लिए जिन प्रमुख मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने/समाधान करने के लिए इन बिंदुओं पर ध्यान कराया आकृष्ट:-

भंडारण के लिए कीटनाशक लाइसेंस वर्तमान में, प्रत्येक विक्रय पते और भंडारण पते के लिए कीटनाशक लाइसेंस की आवश्यकता अलग-अलग है। कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर एक से अधिक लाइसेंस नहीं बनवा सकता। ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए कि कीटनाशक लाइसेंस पर भंडारण पते जोड़े जा सकें, जैसा कि बीज और उर्वरक व्यापार में किया जा रहा है। यदि यह प्रावधान किया जाता है, तो व्यापारी एक ही लाइसेंस के तहत अपना कीटनाशक व्यवसाय चला सकेंगे।

मृतक खुदरा विक्रेताओं के परिवार के सदस्यों के लिए सर्टिफिकेट कोर्स कीटनाशक नियम, 1971 के नियम 14 के उपनियम (1) में केंद्र सरकार एक प्रावधान जोड़ने की योजना बना रही है, जिसके तहत मौजूदा खुदरा विक्रेता की मृत्यु की स्थिति में, मृतक खुदरा विक्रेता का परिवार का सदस्य मृतक खुदरा विक्रेता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर लाइसेंस को उसके नाम पर स्थानांतरित करने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकता है। इस प्रावधान के कारण विश्वविद्यालयों के लिए सदस्य (जो मुश्किल से एक या दो हो सकते हैं) को प्रशिक्षण देना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसे एक आसान प्रक्रिया बनाने के लिए एक नया प्रावधान बनाया जा सकता है, जिसके तहत मौजूदा लाइसेंस धारक का परिवार का सदस्य अभी ही सर्टिफिकेट कोर्स कर सकता है और लाइसेंस धारक की मृत्यु का इंतजार नहीं करना पड़ता। यह विश्वविद्यालयों के लिए भी अच्छा काम करेगा क्योंकि उन्हें बैच के लिए पर्याप्त सदस्य मिलेंगे। सदस्यों को एनआईपीएचएम के माध्यम से ऑनलाइन यह कोर्स करने और लाइसेंस के लिए आवेदन करने में भी सक्षम होना चाहिए।

लाइसेंस में लाइसेंस धारक के साथ नामिती को जोड़ना मौजूदा लाइसेंस/जारी किए गए लाइसेंस में लाइसेंस धारक के साथ नामिती/नामितियों को जोड़ने का प्रावधान किया जा सकता है। इस प्रावधान के माध्यम से एक सदस्य को अपनी पहचान और मौजूदा लाइसेंस धारक के साथ संबंध साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

लाइसेंस में एक कीटनाशक अणु जोड़ने के लिए 500 रुपये का शुल्क वर्तमान में, कीटनाशक नियम कहते हैं कि कृषि इनपुट डीलरों को अपने लाइसेंस में जोड़ने की योजना बनाने वाले प्रत्येक नए अणु (जिस अणु को वे बेचने की योजना बनाते हैं) के लिए 500 रुपये का भुगतान करना होगा। हर साल कीटनाशक कंपनियां बाजार में नए अणु पेश करती हैं। इतनी सारी कंपनियां इतने सारे नए अणु लेकर आ रही हैं, इन अणुओं को लाइसेंस में जोड़ने के लिए इतनी बड़ी राशि का भुगतान करना लाइसेंस धारकों के लिए बिल्कुल भी वहनीय नहीं है और अंततः में किसानों को दी जाने वाली उनकी सेवा को प्रभावित करता है। इसके बजाय, किसी भी नए अणु को लॉन्च करने पर निर्माता से एकमुश्त शुल्क लिया जाना चाहिए। उपरोक्त परिस्थिति में, मैं इन चुनौतियों को कम करने के लिए मुद्दों की जांच कर कृषि इनपुट डीलरों की दक्षता में काफी सुधार होगा, और अंततः बड़े कृषि समुदाय को लाभ होगा। इन बिंदुओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इनके निराकरण से कृषि और कृषि व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई है। जागरूक कृषि आदान विक्रेता संघ जिला इंदौर के अध्यक्ष श्री कृष्णा दुबे व मध्य प्रदेश कृषि आदान विक्रेता संघ भोपाल के समस्त पदाधिकारी साथियों की ओर से भी दिल्ली में आयोजित बैठक में उठाए गए मुद्दों को कृषि आदान व्यापारियों के हित में बताते हुए एसोसिएशन के व्यापार और व्यापारियों के हित में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए संगठन पदाधिकारियों का आभार जताया है।

क्या इस बार आफत की बारिश साबित होगी? अभी और मानसून बरसने के अनुमान ने बढ़ाई चिंता

हलधर किसान

नई दिल्ली। इस बार देश में मॉनसून के बादल जमकर बरस रहे हैं। जून में धीमी शुरुआत के बाद जुलाई में जमकर बारिश हुई है और अगस्त में भी मानसून पूरी रफ्तार में है। लगातार बारिश से जहां नदी, तालाब, बांध का जलस्तर बढ़ गया है तो वहीं खेतों में भी अब जलजमाव की स्थिति होने लगी है। ऐसे में एक नई रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि इस बार मॉनसून की वापसी देर से हो हो सकती है। यानि बारिश इस बार न केवल सामान्य से ज्यादा हो रही है साथ ही सामान्य से ज्यादा वक्त तक चलने का भी अनुमान है। आईएमडी पहले ही कह चुका है कि मॉनसून के बाकी के दो महीने बारिश सामान्य से अधिक रह सकती है। नए रिपोर्ट के बाद आशंका बन गई है कि अगर फसल पकने के वक्त जमकर बारिश होती है तो धान सहित कई फसलों को नुकसान हो सकता है।

क्या है रिपोर्ट में अनुमान

मौसम विभाग के दो अधिकारिक सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि इस सत्र मॉनसूनी बारिश की वापसी देरी से हो सकती है। रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि सितंबर के महीने में देश में कम दबाव का सिस्टम बनने की वजह से मॉनसून तय वक्त से कुछ ज्यादा समय तक देश में बना रह सकता है। इस नए डेवलपमेंट के साथ चिंताएं भी बन गई हैं क्योंकि सितंबर के मध्य के साथ ही फसलों का पकना भी शुरू होता है। ऐसे समय में बारिश होना फसलों को खराब भी कर सकता है। अगर मध्य सितंबर में भी मॉनसून रफ्तार में बना रहता है तो इस दौरान पकने वाली धान, कपास, सोयाबीन, मक्का और दालों की फसल पर इसका बुरा असर पड़ सकता है।

हालांकि दूसरी तरफ बारिश से जमीन की नमी बढ़ेगी और इसका फायदा सर्दियों में बुआई यानें रबी वाली फसलों को मिल सकता है। जिसमें गेहूं अहम है। ऐसे में नजर सितंबर की बारिश के पैटर्न पर रहेगी क्योंकि इसका खरीफ फसलों की पैदावार और अगली फसल की बुआई दोनों पर ही असर दिखेगा। बारिश को लेकर मौसम विभाग इसी हफ्ते अपने अनुमान जारी करेगा।

कब वापस होता है मॉनसून

भारत में मॉनसून की बारिश जून की शुरुआत के शुरू होती है जुलाई की शुरुआत तक मॉनसून पूरे भारत को कवर कर लेता है। मॉनसून की वापसी सितंबर के मध्य से शुरू होती है और अक्टूबर के मध्य तक मॉनसून का खोजन खत्म हो जाता है। इस बार आशंका है कि मॉनसून की वापसी सितंबर अंत तक खिंच सकती है। वहीं जून में मॉनसून की शुरुआत के साथ अब तक पूरे देश में बारिश सामान्य से 7 फीसदी अधिक रही है, मध्य भारत में बारिश सामान्य से 17 फीसदी अधिक रही है। हालांकि पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में बारिश सामान्य से कम रही है।

सितंबर में भी तेज बारिश के आसार

मौसम विभाग ने सितंबर में भी देश के विभिन्न हिस्सों में भारी से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी के डेली बुलेटिन के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

कुल मिलाकर, अगले हफ्ते के अधिकांश दिनों में मध्य और उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है।

सितंबर में अधिक बारिश का अनुमान

मानसून इस समय देश भर में काफी मेहरबान है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक सभी पहाड़ी राज्यों में आफत की बारिश हो रही है। वहीं गुजरात से लेकर राजस्थान तक बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इन दोनों राज्यों में काफी बड़े इलाके में पानी भर गया है। गुजरात में तो रात लोगों की इस बाढ़ और बारिश की वजह से जान भी जा चुकी है। मौसम विभाग की मानें तो भारत में इस समय दो सक्रिय मौसम सिस्टम के कारण भारी बारिश हो रही है । पहला सिस्टम उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और उससे सटे पूर्वी राजस्थान पर बना एक डिप्रेशन है, जबकि दूसरा दक्षिण खाड़ीदेश और उसके आसपास के इलाकों पर बना एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण है। भारतीय मौसम विभाग ने सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान जताया है। सितंबर के पहले हफ्ते तक ला नीना परिस्थितियां अनुकूल हो सकती है, जिससे मानसूनी बारिश में वृद्धि हो सकती है। हालांकि, मानसून के दूसरे हिस्से में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है।

सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश अव्वल दो साल बाद फिर मिला सोया प्रदेश का ताज

देश में 41.92 प्रतिशत योगदान, यहां 5.47 फीसदी मिलियन टन सोयाबीन का उत्पादन, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर

हलधर किसान

भोपाल। मध्य प्रदेश ने सोयाबीन उत्पादन मामले में अपने निकटतम प्रतियोगी राज्यों महाराष्ट्र और राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए फिर से 'सोयाबीन प्रदेश' बनने का ताज हासिल कर लिया है। भारत सरकार के जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश 5.47 मिलियन टन सोयाबीन उत्पादन के साथ पहले नंबर पर आ गया है। देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान 41.92 प्रतिशत है, महाराष्ट्र 5.23 मिलियन टन के साथ दूसरे नंबर पर है। देश के कुल उत्पादन में महाराष्ट्र का योगदान 4.1 प्रतिशत है जबकि राजस्थान 1.17 मिलियन टन उत्पादन के साथ तीसरे नंबर पर है। देश के कुल सोया उत्पादन में राजस्थान का योगदान 8.96 प्रतिशत है।

पिछले दो सालों में मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादन में कमी आने से मध्य प्रदेश पिछड़ गया था। वर्ष 2022.23 में महाराष्ट्र 5.47 मिलियन टन उत्पादन के साथ प्रथम स्थान पर था और देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में 42.12 प्रतिशत का योगदान था और जबकि मध्य प्रदेश 5.39 मिलियन टन के साथ दूसरे नंबर पर था। देश के कुल सोया उत्पादन में योगदान 41.50 प्रतिशत था। इसके पहले 2021.22 में भी महाराष्ट्र 6.20 मिलियन टन उत्पादन के साथ प्रथम स्थान पर था और देश के सोयाबीन उत्पादन में 48.7 प्रतिशत का योगदान था, जबकि मध्य प्रदेश 4.61 मिलियन टन के साथ दूसरे नंबर पर था।

देश के कुल उत्पादन में इसका योगदान 35.78 प्रतिशत था। इसके एक साल पहले 2020.21 में मध्य प्रदेश 5.15 मिलियन टन उत्पादन के साथ पहले स्थान पर रहा था और देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में 45.05 प्रतिशत का योगदान था। इस साल महाराष्ट्र 4.6 मिलियन टन उत्पादन के साथ दूसरे नंबर पर था और राजस्थान तीसरे नम्बर पर था।

उतार.चढ़ाव

पिछले वर्षों में सोयाबीन उत्पादन और क्षेत्रफल में उतार.चढ़ाव होता रहा। सोयाबीन के क्षेत्रफल में वर्ष 2018.19 की तुलना में वर्ष 2019.20 में 14.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सोयाबीन क्षेत्रफल 2018.19 में 5019 हजार हेक्टेयर था जो 2019.20 में बढ़कर 6194 हजार हेक्टेयर हो गया। इसी दौरान सोयाबीन का उत्पादन 2018.19 में 5809 हजार मीट्रिक टन था जो 2019.20 में कम होकर 3856 हजार मीट्रिक टन हो गया। सोया उत्पादन में 33.62 प्रतिशत की कमी आई।

प्रदेश में सोयाबीन का रकबा

प्रदेश में सोयाबीन का रकबा 2022.23 की अपेक्षा 2023.24 में 1.7 प्रतिशत बढ़ा और क्षेत्रफल पिछले साल 5975 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 2023.24 में 6679 हजार हेक्टेयर हो गया है। सोयाबीन का क्षेत्रफल बढ़ने से उत्पादन भी बढ़ा। पिछले साल 2022.23 में सोयाबीन उत्पादन 6332 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर 2023.24 में 6675 हजार मीट्रिक टन हो गया।

केले के फलों के फटने का क्या होता है कारण, जानें कैसे करें बचाव

हलधर किसान. भोपाल. केले के फलों का अत्यधिक फटना, केले उत्पादकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा होता है, लेकिन इसे कृषि कार्यों, विभिन्न प्रकार के चयन और पर्यावरण निगरानी के संयोजन के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। फलों के फटने के कारणों को समझकर और उचित प्रबंधन रणनीतियों को लागू करके केला उत्पादक किसान नुकसान को कम कर सकते हैं, फलों की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं और अपनी समग्र उपज और लाभप्रदता बढ़ा सकते हैं। सबसे ज्यादा ये समस्या केले के पूसा प्रजाति में देखी जाती है। केले के छिलके फट जाते हैं, जिससे न केवल फलों का आकर्षण कम हो जाता है बल्कि इससे फलों में कीटों और बीमारियों के प्रकोप की संभावना भी बढ़ जाती है। केले के फटने के पीछे का सबसे बड़ा असर पर्यावरण की परिस्थितियां हैं, जिसमें जरूरत से ज्यादा बारिश है। जब ज्यादा बारिश होती है तो इससे फलों की तेजी से वृद्धि होती है।

इससे बाद में फलों का वजन तेजी से बढ़ता है। गर्म दिन के बाद जब ठंडी रात आती है तो तापमान में अत्यधिक उतार.चढ़ाव के कारण फलों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। इसी से केले के फल फट जाते हैं।

कैसे करें बचाव

. केले की कुछ किस्मों में अन्य की तुलना में दरार पड़ने की आशंका ज्यादा रहती है। इसलिए पर्यावरण की परिस्थिति और स्थानीय जलवायु के अनुरूप की किस्मों का चयन करना चाहिए।

. मिट्टी की नमी भी समान नहीं रखना केले के फटने के पीछे का कारण हो सकता है। इसलिए अपर्याप्त सिंचाई या अनियमित पानी से फसलों को बचाकर रखें। ड्रिप सिंचाई प्रणालियां जैसी उचित तकनीक का इस्तेमाल करें।

. केले के पौधे से बेहतर उत्पादन पाने के लिए पौधे को उचित और संतुलित मात्रा में पोषक तत्व देना जरूरी है, इसके साथ ही समय.समय पर मिट्टी की उर्वरकता का भी परीक्षण करवा लेना चाहिए।

. एन्थ्रेक्नोज या नेमाटोड जैसे कीट और रोगों के कारण फसल कमजोर होती है, जिसके कारण भी केले फट सकते हैं। इसलिए कीटों और रोगों से फसलों को बचाकर रखना जरूरी है।

.एकीकृत कीट प्रबंधन तकनीक का इस्तेमाल करके केले के पौधे को रोगों और कीटों से बचाकर बेहतर फसल हासिल की जा सकती है।

. समय.समय पर केले के पौधों की छंटाई करना जरूरी है। अत्यधिक पत्तियों की कटाई करने से बचें।

. केले की खेती करने के लिए मौसम पर नजर बनाए रखना जरूरी है। क्योंकि अत्यधिक बारिश से फसलों को नुकसान हो सकता है। इसलिए अत्यधिक नमी को रोकने के लिए पहले से ही व्यवस्था कर लें।

धान में तना छेदक कीट का कैसे करे नियंत्रण वैज्ञानिकों ने बताए प्रभावी उपाए

हलधर किसान. रायपुर। कृषि विज्ञान केन्द्र, सुकमा के पौध रोग वैज्ञानिक राजेन्द्र प्रसाद कश्यप, कीट वैज्ञानिक डॉ. योगश कुमार सिदार, कृषि अभियांत्रिकी वैज्ञानिक डॉ.परमानंद साहू व चिराग परियोजना के एसआरएफ यमलेशवर भोयर ने बताया कि वर्तमान में मैदानी भ्रमण के दौरान धान के खेत मे तना छेदक कीट का आक्रमण दिखाई दे रहा है। इस कीट की चार अवस्था होती है अण्डा, इल्ली, शंखी व तितली। मादा तितली पत्तियों के पास समूह मे अंडे देती है। अंडे से इल्ली निकलती है जो हल्के पीले रंग की होती है। इल्ली पहले पत्तियों को खाते हुए धीरे.धीरे गोभ के अंदर प्रवेश करती है, जिससे पौधे की बढ़वार रूक जाती है। इसके नियंत्रण के लिए रोपाई करते समय पौधे के ऊपरी भाग को थोड़ा सा काटकर रोपाई करना चाहिए। खेतो एवं मेड़ो को खरपतवार मुक्त रखें। संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों का उपयोग करें। खेत की समय.समय पर निगरानी करें तथा अण्डे दिखाई देने पर नष्ट कर दे। खेतो मे चिड़ियो के बैठने के लिए टी आकार की पक्षी मिनार लगाए। नर तितली को आकर्षित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप लगाए। रात्रि चर कीट को पकड़ने के लिए प्रकाश प्रपंच या लाइट खेतों में लगाए। अण्ड परजीवी ट्राइकोग्रामा जॉपोनिकम के 50 हजार अण्डे प्रति हेक्टेयर की दर से दो से तीन बार खेत में छोड़ना चाहिए। उस समय रासायनिक कीटनाशक का स्प्रे ना करें। नीम अजेडिरेक्टीन 1500 पी पी एम का 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। दानेदार कीटनाशकों का छिड़काव गभोट वाली अवस्था से पहले करना चाहिए।

बारिश रुकने व मौसम खुला होने पर कोई एक कीटनाशक का प्रयोग करें। क्लोरेंट्रानिलिप्रोएल 0.4 प्रतिशत जी आर 10 किलो प्रति हेक्टेयर या क्लोरेपायरीफॉस 20 ईसी.1250 मिली. प्रति हेक्टेयर या कर्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 50 प्रतिशत एसपी 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर या क्लोरेंट्रानिलिप्रोएल 18.5 प्रतिशत एससी 150 मिली प्रति हेक्टेयर या फिप्रोनिल 5 प्रतिशत एस.सी 1000.1500 मिली. प्रति हेक्टेयर या फ्लूबेंडामाइड 20 प्रतिशत डब्ल्यू जी. 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर का उपयोग करके प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक न होने पर 15 दिन बाद दूसरे कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केन्द के वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर ही दवाईयों का छिड़काव करें।

रसायनिक खेती छोड़, प्राकृतिक खेती को दिया बढ़ावा, होने लगा लाखों का मुनाफा

8 एकड़ रकबे में अमरुद, हल्दी और अदरक की खेती से रजूर के प्रगतिशील किसान रामचंद्र ले रहे एक करोड़ रुपए की उपज

छोटे से गांव के अमरुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का है सपना

हलधर किसान

(सफलता की कहानी)
कांतिलाल कर्मा, खरगोन।

बदलते वक्त के साथ खेती में भी बदलाव आ रहा है। निमाड़ अंचल वैसे तो कपास, मिर्च के लिए जाना जाता है, लेकिन बागवानी फसलों से भी अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। इसका उदाहरण बने है, जिला मुख्यालय से करीब 30 किमी दूर बसे ग्राम रजूर के प्रगतिशील किसान रामचंद्र पाटीदार।

8 एकड़ खेत में लगे अमरुद (जाम) के के साथ ही हल्दी, अदरक की फसल से न केवल हर साल करीब एक करोड़ रुपए की आमदनी ले रहे है, बल्कि 30 लोगों को स्थायी रोजगार भी दे रहे है। पाटीदार ने अपने अमरुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का सपना देखा है और उस सपने को पूरा करने की दिशा में आगे भी बढ़ गए है। उन्होंने एक कंपनी बनाकर अपनी उपज खुद एक्सपोर्ट करने के प्रयास तेज किए है।

श्री पाटीदार ने बताया 2018 तक रसायनिक खेती की। मिर्च में बेहतर उत्पादन भी लिया लेकिन समय के साथ दिनोंदिन घटती मिट्टी की उर्वरा शक्ति और घटते उत्पादन से यह खेती घाटे का सौदा साबित होने लगी। इसके बाद जब प्राकृतिक खेती की ओर रुख किया तो फिर पीछे पलटने का अवसर नहीं मिला और आज वह न केवल गांव बल्कि जिले और राष्ट्रीय स्तर पर प्रगतिशील किसान की पहचान बनाने के साथ ही अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्त्रोत बन गए है।

यू-ट्यूब चैनल के जरिये किसानों को करते है प्रेरित

44 वर्षीय श्री पाटीदार ने बताया कि उन्होंने बागवानी की बारीकियां यू-ट्यूब और किताबों के माध्यम से सीखे और फसल से लाभ कमा रहे है, अन्य किसानों को भी बेहतर उत्पादन मिले इसके लिए यू- ट्यूब पर खुद के नाम से चैनल चलाकर रोजाना बागवानी के रखरखाव की जानकारी साझा करता हू, जिससे देशभर के किसान जुड़े होकर प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे है। किसानों से अपील की है कि वह रासायनिक खादों के बजाय प्राकृतिक खेती करें, क्योंकि प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो प्रकृति भी हमारा साथ देगी।

खासकर की बागवानी की खेती में ज्यादा फायदा है। श्री पाटीदार तो सफल किसान है साथ ही उनके बेटे अश्विन जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के प्रयास न करते हुए पिता की खेती को ही आगे बढ़ाने में रुचि दिखाई है।

एक किसान की सफलता से मिली प्रेरणा

श्री रामचंद्र अपनी सफलता का श्रेय खुद की मेहनत के साथ ही अपने मामा हीरालाल और कमलेश पाटीदार निवासी इटारनपुरा को देते है। श्री पाटीदार का कहना है कि मैं 2018 तक मिर्च की खेती करता था, दिनोंदिन उत्पादन घटने से कर्जदार होने की स्थिति बन गई थी। ऐसे में मेरे मामा मेरे पास एक पेपर कटिंग लाए, जिसमें अमरुद की फसल से किसान के मालामाल होने की कहानी प्रकाशित थी। उस अखबार में अमरुद के पौधे कहां से मिलेंगे, किस किस्म के पौधे लगाने है। इसकी जानकारी भी थी।

साल- दर साल बढ़ रहा मुनाफा

श्री पाटीदार ने बताया शुरुआत में उन्होंने 50- 50 याने आधी मात्रा रसायनिक एवं आधी प्राकृतिक तरीके से रखरखाव किया। जिसमें उत्पादन और गुणवत्ता भी अच्छी रही। इसके बाद धीरे- धीरे- प्राकृतिक तरीके का रेशो बढ़ाया और रसायनिक का उपयोग कम करने लगे। अपने खेत में शुरुआत दौर में वीएनआर बीही किस्म का अमरुद लगाया, करीब ढाई साल में पौधा तैयार होकर उपज देने लगा। शुरुआत में कम बचत रही, लेकिन समय के साथ यह बढ़ती गई और बारहमासी होने वाले अमरुद के साथ हल्दी और अदरक की फसल से आज एक करोड़ रुपए का टर्नओवर हो गया है। हालांकि इसमें करीब 25 से 30 लाख रुपए का खर्च भी होता है। वे अपनी उपज सीधे दिल्ली की मंडियों में पहुंचाते है, हालांकि वहां की मंडी में मिल रहे दामों से भी वे संतुष्ट नहीं है। पाटीदार ने बताया कि वह एफपीओ के जरिये अपनी उपज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वयं बेचने का प्रयास कर रहे है, जिससे सीधा मुनाफा उन्हें और उनसे जुड़े किसानों को मिले। इस काम से प्रति एकड़ लाखों रुपए का फायदा होता है। इतना ही नहीं वर्षभर 30 मजदूर यहां हमेशा कार्यरत रहते है।

बीज भंडार

हमारे यहाँ पर सभी कम्पनियों के उच्च क्वालिटी के सब्जी बीज एक ही छत के नीचे उचित दाम पर मिले है!

ब्रांच: खरगोन/खंडवा /कुक्षी/ महू /राजपुर/अंजड/धामनोद/इंदौर/जबलपुर/मंडलेश्वर/ मनावर/ कालापीपल /कसरावद पूंजापुरा/ छिंदवाड़ा। बीज भंडार की फ्रेंचाईसी लेने के लिए संपर्क करे - 8305103633, 7879428271

स्वामी विवेक जैन, प्रकाशक विवेक जैन, मुद्रक कैलाश महाजन द्वारा गोपाल प्रिंटिंग प्रेस, तिलक पथ, खरगोन से मुद्रित एवं 26/1, विवेकानंद कॉलोनी, वार्ड नंबर 5, खरगोन से प्रकाशित, संपादक विवेक जैन।.RNI No. MPHIN/2022/85285, मोबा. नं.98262 25025, 94254 89337 (समस्त प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र खरगोन रहेगा)।